

संक्षिप्त समाचार

गिरिबाला और समर्थ को कोर्ट लेकर पहुंची सीबीआई, नहीं की रिमांड बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। मॉडल-अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के हाइप्रोफाइल मामले में सीबीआई ने मंगलवार दोपहर पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को विशेष अदालत में पेश किया। यहां आरोपी गिरिबाला सिंह समर्थ सिंह की रिमांड मांगने से इनकार कर दिया है। त्विषा शर्मा की 12 मई को सदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती जांच के बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। एजेंसी ने पांच दिन पूर्व मिली रिमांड अवधि के दौरान त्विषा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह से पूछताछ की है, लेकिन साजिश की पूरी कड़ियां जोड़ने के लिए समर्थ को दोबारा रिमांड पर लेना जरूरी माना जा रहा है। सीबीआई शादी के समय त्विषा को मायके और रिश्तेदारों से मिले सोने के उपहारों (स्त्रीधन) को जब्त करने की तैयारी में है। इसके लिए एक जौहरी को भी तलाब किया है, जो ब्यामद होने वाले जेवरातों की शुद्धता और उसकी मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करेगा।

800 रुपये में बिक रहा लेबर रूम का वीडियो, अस्पताल में वायरल फुटेज ने मचाई सनसनी

राजकोट। गुजरात से महिलाओं की प्राइवसी (निजता) से खिलवाड़ का एक बेहद धिनीता और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अस्पतालों के लेबर रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक कर, प्रसव (डिलिवरी) और इलाज के दौरान महिलाओं के बेहद आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन बेचे जा रहे थे। साइबर क्राइम की इस गंभीर घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह पूरा मामला 17 फरवरी 2025 को तब उजागर हुआ, जब सोशल मीडिया पर एक अस्पताल के लेबर रूम का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में बेड पर लेटी एक गर्भवती महिला को नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। वीडियो के नीचे लिखा था पूरा वीडियो देखने के लिए यहां संपर्क करें।और इसके साथ एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया था। टेलीग्राम पर यह गिरोह पैसे लेकर महिलाओं के मेडिकल चेकअप से लेकर डिलिवरी तक की पूरी फुटेज बेच रहा था। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत के बाद हरकत में आई अहमदाबाद पुलिस और साइबर टीम ने जब जांच शुरू की, तो उनके होश उड़ गए। पति-पत्नी और बेटे की सिर कूचकर हत्या

प्रयागराज। कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका में हीवेट रोड चौराहे पर एक घर में पति-पत्नी और उनकी बेटे की लाश मिली। मकान पिछले दो दिनों से बंद था। वहां से बन्दूक आने पर पड़ोसियों ने 112 पर जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा। पहले तो पिता और बेटे की लाश मिली। पास में ही उनकी पत्नी की भी लाश मिली। तीनों के सिर पर जख्म के गहरे घाव मिले। पुलिस ने जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कही है।

अग्निकांड से फिर दहली दली

मालवीय नगर रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 की मौत

नई दिल्ली। एजेंसी

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मृतकों और घायलों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, जिस इमारत में आग लगी उसमें रेस्टोरेंट के साथ-साथ ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध थी। वहां ठहरे अधिकांश लोग ऐसे थे जिनके परिजनों का इलाज पास स्थित हास्पीटल में चल रहा था। इसी वजह से वे अस्थायी रूप से वहां रह रहे थे। हादसे के बाद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, होटल के पास केवल 6 कमरों के संचालन का लाइसेंस था, जबकि इमारत में 25 से अधिक कमरे बनाए गए थे। यदि यह जानकारी जांच में सही पाई जाती है, तो यह भवन नियमों और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन का मामला हो सकता है। बताया जा रहा है कि इमारत से बाहर निकलने के लिए केवल एक मुख्य रास्ता था, जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगों के सुरक्षित निकास में कठिनाई हुई। कुछ लोग बेसमेंट में भी मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के दौरान बेसमेंट के बाहरी गेट पर ताला लगा होने की बात भी सामने आई है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फयर अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण जानकारीयां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 8:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। अधिकारी के अनुसार, शुरुआती प्रतिक्रिया के तहत घटनास्थल पर 7 फायर टैंडर भेजे गए थे, जबकि अन्य आवश्यक यूनिट्स भी रास्ते में थीं। सभी जरूरी संसाधन जल्द ही मौके पर पहुंच गए और दमकलकर्मियों ने तेजी से बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि टीम के घटनास्थल पर पहुंचते ही इमारत में फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। संबंधित भवन



अग्निकांड में एक ही परिवार के 8 लोगों की गई जान

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं, जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से भारत आए थे। दिल्ली अग्निरक्षम विभाग और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, होटल के रेस्टोरेट में सुबह 8:50 बजे आग लगी। जिसके बाद भीषण आग ने ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के रूम और बेसमेंट को अपने चपेट में ले लिया। इस भयावह हादसे में गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये परिवार मैक्स हॉस्पिटल में एक परिजन का इलाज करने के लिए लिए आए हुए थे। घटना के वक्त ये सभी लोग होटल में नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही इस हादसे की जानकारी सामने आई, मालवीय नगर स्थित होटल में ठहरे हुए लोगों के परिजन मैक्स अस्पताल के बाहर जुट गए। अस्पताल में कुल 39 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिनमें 18 की मौत हो चुकी थी। दिल्ली के महावीर एनक्लेव के रहने वाले प्रेम बंसल भी जब यहां पहुंचे तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में बेटी-दामाद समेत उनके परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। प्रेम बंसल के दामाद विवेक अग्रवाल गुरुग्राम के सेक्टर-46 के निवासी थे। विवेक अग्रवाल सेक्टर-46 के मकान नंबर 3169 में परिवार के साथ रहते थे। ऐसे से वह सीए थे। इस मकान के ग्रांडफ्लोर पर विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, पिता राधेश्याम अग्रवाल, बेटी जीविशा और वारिया के साथ रहते थे। विवेक के पिता राधेश्याम की इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट किया गया था। बुधवार को विवेक के मौसा-मौसी पिता से मिलने के लिए दिल्ली आए थे।

एक बहुमंजिला संरचना है, जिसमें एक बेसमेंट, ग्रांडफ्लोर और पांच ऊपरी मंजिलें हैं। मालवीय नगर के हौज रानी क्षेत्र स्थित एक होटल में लगी भीषण आग की घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे से वे बेहद व्यथित हैं और उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। उपराज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति उनकी हार्दिक संवेदनाएं हैं। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की

कामना करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि पुलिस, सिविल और अग्निशमन बचाव दल की टीमों घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। सभी संबंधित एजेंसियां प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं।उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए, राहत कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहे तथा घटना की गहन जांच

पिता बनने की खुशी मनाने घर आए सेना के जवान की हादसे में मौत

झुंझुनूं। नियति का क्रूर खेल किसे कहते हैं, इसका एक ऐसा कलेजा चीर देने वाला मंजर राजस्थान के झुंझुनूं जिले के इंडाली गांव में देखने को मिला, जिसने हर आंख को नम कर दिया। जिस घर में अभी महज 17 दिन पहले गुंजी किलकारियों का उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार मच गई। भारतीय सेना के 11 ग्रेनेडियर्स यूनिट में तैनात 29 वर्षीय जांबाज जवान सुनील कुमार, जो अपने नवजात बेटे के नामकरण संस्कार (दर्शोष्ण) की खुशियां मनाने छुट्टी पर घर आए थे, एक सड़क हादसे में ज़िंदगी की जंग हार गए। जब सोमवार को उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिफ्टकर पैतृक गांव पहुंचा।

जबरन मजदूरी का लगाया आरोप

राष्ट्रपति डोनाल्ड का भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ बम!

नई दिल्ली/ एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर भारत को तगड़ा झटका दे सकते हैं। जी हां.. डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया पर टैरिफ बम फेंड़ने की तैयारी में हैं। लिहाजा इससे अमेरिका को घाटा हो रहा है। लिहाजा इन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाया जाए। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि 1974 के अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 60 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियां और कार्यप्रणालियां अमेरिकी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। यूएसटीआर के अनुसार इन देशों द्वारा जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात को प्रभावी ढंग से रोकने में विफल रहने के कारण अमेरिकी

खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है। यूएसटीआर का कहना है कि इन देशों ने कथित तौर पर जबरन श्रम (फोर्स्ड लेबर) से तैयार वस्तुओं के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं। लिहाजा इससे अमेरिका को घाटा हो रहा है। अमेरिका भारी-भरकम नया टैरिफ भारत पर लगा सकता है। अमेरिका कम से कम 10 फीसदी का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। वहीं 12.5व टैरिफ रेट भी पहुंच सकता है। उनका ये प्रपोजल जबरन श्रम प्रथाओं की जांच के बाद आया है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बातचीत के बीच ये प्रस्ताव लाया गया है। इसका असर दोनों देशों के व्यापार समझौता पर पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने भारत और चीन सहित 60 देशों के



कारोबार प्रभावित हो रहा है। लिहाजा इन देशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिहाजा इन देशों के खिलाफ ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में भारत और चीन का नाम शामिल है। दोनों देशों के खिलाफ ट्रंप 12.5 फीसदी का टैरिफलगा सकते हैं। इन दोनों देश के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील

और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से आने वाले सामानों पर भी 12.5 फीसदी का टैरिफ लगा सकता है। जबकि कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन, ताइवान और ब्रिटेन समेत अन्य देशों से आयात पर 10 फीसदी की टैरिफ लागू हो सकता है। यूएसटीआर ने बताया कि इस मामले की

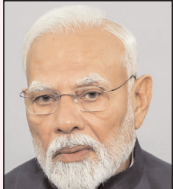
जांच 12 मार्च को शुरू की गई थी। जांच के दौरान करीब 60 गवाहों के बयान लिए गए और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान लगभग 500 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एजेंसी ने अपने निष्कर्ष तैयार किए हैं। जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध नहीं होने से वैश्विक स्तर पर श्रम शोषण खत्म करने के प्रयास कमजोर पड़ते हैं। इससे कम लागत पर उत्पादन करने वाले उत्पादों को अनुचित लाभ मिलता है। बाजार की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और उन कंपनियों को नुकसान पहुंचता है जो जबरन श्रम का उपयोग नहीं करती। कई व्यापारिक मतभेदों के बावजूद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है।

जबरन मजदूरी का लगाया आरोप

अमेरिकी सरकार ने यह कठोर कदम उठाने के पीछे मानवाधिकारों और श्रम नियमों का हवाला दिया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन 60 देशों में जबरन मजदूरी के जरिए सामान तैयार किया जाता है और इन देशों ने ऐसे सामान के आयात पर लगे प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू नहीं किया है। अमेरिका का तर्क है कि इससे अमेरिकी कामगारों को वैश्विक बाजार में 'असमान और अनुचित' प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यूएस ट्रेड रियेगुलैटिव के राजदूत जैमिसन ग्रीयर ने इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमारे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों का जबरन मजदूरी से बने सामान को रोकने में विफल रहना 'अस्वीकार्य' है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक व्यापार अजाने में भी जबरन मजदूरी को बढ़ावा न दे।

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में लोगों की मौत को अत्यंत दुःख बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है और राहत एवं बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री फण्ड से हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया शोक



मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिजनों को दीं संवेदनाएं

मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही सभी संबंधित आपातकालीन एजेंसियों को तत्काल सक्रिय कर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एमएलसे सेवा और अन्य अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल बचाव अभियान चलाया। उनकी त्वरित कार्रवाई के कारण प्रभावित भवन से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका और अनेक लोगों की जान बचाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना में हुई जनहानि से वह अत्यंत व्यथित हैं।



टीएमसी टूटी 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया

रितब्रता बनर्जी को विधायक दल का अब नेता चुना गया

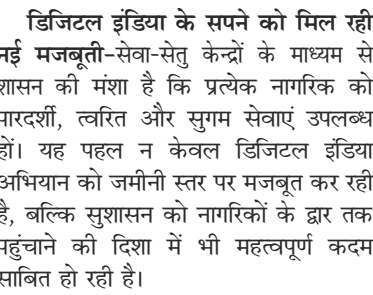
नई दिल्ली/ एजेंसी

इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से आई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट गई है। 58 बागी विधायकों ने अलग गुट बनाया है। 58 बागी रू ने पार्टी से निकाले गए विधायक रितब्रता बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित किया। बागी विधायकों के दल ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर अपना समर्थन पत्र भी सामने अब अपनी खुद की बनाई पार्टी टीएमसी से भी कटौल खोने की संभावना बन गई है। 15 साल बाद असली टीएमसी पार्टी का दावा



किया। इसी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी दो गुटों में बंट गया है। बागी विधायकों के इस कदम से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी को सामने अब अपनी खुद की बनाई पार्टी टीएमसी से भी कटौल खोने की संभावना बन गई है। 15 साल बाद असली टीएमसी पार्टी का दावा

बंगाल की सत्ता से दूर होने के बाद ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी से भी हाथ धो सकती हैं। बैठक में 58 बागी एमएलए ने रितब्रता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना। वहीं जवेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता बनाया गया है। जबकि अखर जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। बता दें कि टीएमसी में टूट की नौव सित्तेचर फर्नीवाड़े के बाद पड़ी।



संपादकीय

पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने प्रतिद्वंद्वी दलों पर स्पष्ट बढ़त बनाते हुए अपनी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। नगर निगमों और वार्डों में मिली सफलता को पार्टी अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर मान रही है। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में जो तस्वीर उभरी है, वह आम आदमी पार्टी (आप) की स्पष्ट कामयाबी को दर्शाती है। अगर इसे जनता के रुख के तौर पर देखा जाए, तो यह अगले

वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों का भी संकेत हो सकती है। हालांकि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और फिलहाल कोई बड़ा असंतोष वहां प्रत्यक्ष देखने में नहीं आ रहा है, इसलिए स्थानीय निकायों के नतीजों में अगर उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को बाकी दलों के मुकाबले काफी मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, तो यह अप्रत्याशित नहीं है।दरअसल, पंजाब के शहरी क्षेत्रों में आप ने अपनी

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब का जनमत, राज्य में उभरी नई राजनीतिक दिशा

व्यापक पहुंच और मजबूत जनाधार बनाया है। अब इन चुनावों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और आठ नगर निगमों में से पांच पर जीत हासिल की। कहा जा सकता है कि इन इलाकों में सरकार के कामकाज को ज्यादातर मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस और भाजपा को भी जितनी सीटें मिलीं, उससे फिलहाल उनकी राजनीतिक जमीन बची होने के संकेत मिलते हैं।गौरतलब है कि पंजाब में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों

सहित कुल 104 स्थानीय निकायों के 1,977 वार्डों के लिए हुए मतदान के नतीजों में आप के 958 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं 397 वार्डों पर जीत के साथ कांग्रेस की भी संतोषजनक उपस्थिति बनी रही। जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 191 और भाजपा ने 172 वार्डों पर जीत हासिल की।जाहिर है, अपने प्रतिद्वंद्वी दलों के मुकाबले आप ने काफी बड़े अंतर से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। पिछले स्थानीय निकाय चुनावों से तुलना करें, तो

तस्वीर में बड़ा फेरबदल हुआ है और आप ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। स्वाभाविक ही आम आदमी पार्टी इसे राज्य में अपनी सरकार के कामकाज और विकास कार्यों पर जनता की मुहर मान रही है।इसी के मद्देनजर पार्टी को लगता है कि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में उसके सामने कोई मजबूत चुनौती नहीं है। मगर यह देखने की बात होगी कि स्थानीय निकायों में उभरे नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। स्थानीय चुनाव अक्सर

क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व से प्रभावित होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में मतदाता राज्य सरकार के समग्र प्रदर्शन, राजनीतिक गठबंधनों और व्यापक जनहित के मुद्दों की भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए निकाय चुनावों के नतीजों को विधानसभा चुनाव का अंतिम संकेत मानना जल्दबाजी होगी। फिर भी इतना जरूर है कि इन परिणामों ने पंजाब की राजनीति में मौजूदा शक्ति संतुलन और मतदाताओं के रुख की एक स्पष्ट झलक पेश कर दी है।

क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोरा बुलबुला है या वास्तविक चुनौती?

ललित गर्ग

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। कृषि क्रांति ने मनुष्य को स्थायित्व दिया, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और श्रम की परिभाषा बदली, सूचना क्रांति ने ज्ञान और संचार की सीमाएं समाप्त कर दीं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की क्रांति मानव इतिहास के एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि, निर्णय क्षमता, रोजगार, सामाजिक संरचना, शासन व्यवस्था और यहां तक कि उसके अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। यही कारण है कि आज विश्वभर में यह बहस तेज हो रही है कि क्या एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगी या वह धीरे-धीरे मनुष्य के महत्व को ही चुनौती देने लगेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मशीनों को चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन कार्यों को भी करने लगी है जिन्हें लंबे समय तक केवल मनुष्य की विशिष्ट क्षमता माना जाता था। लेखन, चित्र निर्माण, संगीत रचना, रोगों का निदान, न्यायिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णय जैसे क्षेत्रों में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने अनेक नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि मशीनें सोचने, सीखने और निर्णय लेने लगेगी तो मनुष्य की विशिष्टता क्या रह जाएगी? यह प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दार्शनिक और नैतिक भी है। मानव अस्मिता का आधार उसकी चेतना, संवेदना, रचनात्मकता और नैतिक विवेक है। एआई के पास विशाल सूचनाओं का भंडार और तीव्र गणनात्मक क्षमता अवश्य है, लेकिन उसके पास अनुभवजन्य चेतना, करुणा, आत्मबोध और मूल्यबोध नहीं है। फिर भी जब मशीनें कविता लिखती हैं, चित्र बनाती हैं और संवाद करती हैं, तब यह भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि वे मनुष्य का स्थान ले सकती हैं। वास्तव में चुनौती यह नहीं है कि मशीनें मनुष्य बन जाएंगी, बल्कि यह है कि कहीं मनुष्य स्वयं मशीनों की तरह व्यवहार करने न लगे। यदि जीवन का प्रत्येक निर्णय गणनात्मक दक्षता और आंकड़ों के आधार पर होने लगे, तो मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य हाशिये पर जा सकते हैं। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि क्या भविष्य में एक नई मानव संरचना का निर्माण होगा? विश्व के अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी चिंतक यह मानते हैं कि आने वाले दशकों में जैविक और डिजिटल तकनीक के बीच की दूरी लगातार कम होगी। मस्तिष्क और कंप्यूटर के प्रत्यक्ष संपर्क, कृत्रिम अंगों, स्मृति-विस्तार तकनीकों और जैव-तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक ऐसे युग की कल्पना की जा रही है जहां मनुष्य और मशीन का सम्मिलित स्वरूप विकसित हो सकता है। यह संभावना जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उतनी ही चिंताजनक भी है। यदि तकनीकी रूप से उन्नत मनुष्य और सामान्य मनुष्य के बीच गहरी खाई बन गई तो सामाजिक असमानता का एक नया रूप



सामने आ सकता है। एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में नियमित और दोहराव वाले कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त हो जाएंगे। विश्व की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों ने लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटाई है। किंतु हाल के अनुभव यह भी बताते हैं कि एआई मानव श्रम का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकी है। जटिल निर्णय, नवाचार, मानवीय संबंधों का प्रबंधन और परिस्थितिजन्य विवेक जैसे क्षेत्रों में मनुष्य की भूमिका अभी भी केंद्रीय बनी हुई है। यहीं पर वैश्विक शोध संस्था गार्टनर की हालिया रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है। गार्टनर ने अपनी नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि एआई अब अत्यधिक अपेक्षाओं के शिखर से आगे बढ़कर मोहभंग के चरण में प्रवेश कर रही है। अनेक कंपनियों ने इससे तत्काल आर्थिक लाभ और उत्पादकता में चमत्कारी वृद्धि की उम्मीद की थी, लेकिन वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिले। परियोजनाओं की ऊंची लागत, आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, गलत या भ्रामक उतर देने की प्रवृत्ति और स्पष्ट उपयोगिता सिद्ध न कर पाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि लगभग एक-तिहाई परियोजनाएं प्रारंभिक चरण के बाद बंद हो सकती हैं क्योंकि वे अपने निवेश के अनुरूप परिणाम देने में असफल रही हैं। यह निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्काल सभी समस्याओं का समाधान बन जाएगी।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि एआई एक हथौड़ी बुलबुला है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति के

प्रारंभिक चरण में उत्साह और अतिशयोक्ति दोनों मौजूद रहते हैं। बाद में वास्तविक उपयोगिता के आधार पर उसका संतुलित विकास होता है। इंटरनेट के साथ भी यही हुआ था। प्रारंभिक उत्साह के बाद अनेक कंपनियां समाप्त हो गईं, लेकिन इंटरनेट स्वयं विश्व व्यवस्था का आधार बन गया। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। अतः इसका अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन भी उचित नहीं है और इसके शीघ्र समाप्त हो जाने की कल्पना भी यथार्थवादी नहीं है। व्यापार जगत में एआई की भूमिका निरंतर बढ़ेगी। उत्पादन, विपणन, ग्राहक सेवा, वित्तीय विश्लेषण और आपूर्ति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होगा। इससे कार्यों की गति और दक्षता बढ़ेगी, किंतु साथ ही कार्यबल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। भविष्य में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समस्या समाधान, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक समझ जैसे गुण अधिक महत्वपूर्ण बनेंगे। इसलिए शिक्षा और कौशल विकास की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना होगा।

प्रशासनिक क्षेत्र में भी एआई शासन की अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की क्षमता रखती है। नीतिगत विश्लेषण, संसाधनों का वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का संचालन तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। यदि नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़ों का अत्यधिक संग्रह और विश्लेषण होने लगे तो निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए तकनीकी दक्षता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। सैन्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग सबसे अधिक चिंताजनक माना जा रहा है। स्वायत्त हथियार प्रणालियां, मानव रहित युद्धक उपकरण और लक्ष्य

चयन करने वाली मशीनें युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल सकती हैं। यदि किसी मशीन को जीवन और मृत्यु का निर्णय करने की शक्ति मिल जाए तो नैतिक और मानवीय प्रश्न अत्यंत गंभीर हो जाएंगे। इसलिए विश्व स्तर पर ऐसी तकनीकों के नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।

इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव जीवन सुरक्षित, संतुलित और सार्थक कैसे बना रहे? इसका उत्तर तकनीक के विरोध में नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण उपयोग में निहित है। एआई को मानव जीवन का स्वामी नहीं, सहायक बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, संवेदनशीलता, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देना होगा। मनुष्य की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, करुणा, सहानुभूति और आध्यात्मिक चेतना ही वे क्षेत्र हैं जिन्हें कोई मशीन प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। साथ ही, वैश्विक स्तर पर ऐसे नियमों और नीतियों की आवश्यकता है जो एआई के विकास को मानव कल्याण की दिशा में नियंत्रित करें। यदि यह तकनीक केवल कुछ शक्तिशाली कंपनियों या राष्ट्रों के हितों तक सीमित रह गई तो असमानता और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत यदि इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास के लिए किया जाए तो यह मानवता के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोल सकती है।

अंततः एआई न तो पूर्णतः वरदान है और न ही अनिवार्य रूप से अभिशाप। यह एक शक्तिशाली साधन है जिसकी दिशा और परिणाम मनुष्य के विवेक पर निर्भर करेंगे। चुनौती मशीनों से नहीं, बल्कि इस बात से है कि क्या मनुष्य अपनी मानवीयता, संवेदनशीलता और नैतिक चेतना को सुरक्षित रख पाएगा।

पत्रकारिता का स्तर

नहीं, सच के प्रति

जिम्मेदारी गिर रही है



भगवान दास मिश्रा

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 180 देशों में 157वें स्थान पर पहुंचना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत छह पायदान नीचे खिसककर 157वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले वर्ष 2025 में भारत 151वें स्थान पर था। रिपोर्ट में भारत को "Very Serious" अर्थात् गंभीर स्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में पत्रकारिता का स्तर गिरा है? या फिर पत्रकारिता के मूल उद्देश्य – सत्य, निष्पक्षता और जनहित – से दूरी बढ़ी है?

आज पत्रकारिता एक मिशन से अधिक व्यवसाय बनती जा रही है। कभी समाचार पत्र और समाचार चैनल जनता की आवाज हुआ करते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में मीडिया संस्थान सत्ता, कॉर्पोरेट और विज्ञापन के दबाव में काम करते दिखाई देते हैं। पत्रकारिता का धर्म सत्ता से प्रश्न पूछना है, न कि सत्ता का प्रवक्ता बन जाना। जब पत्रकार का कलम सवाल पूछना छोड़ देता है, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक केवल पत्रकारों की सुरक्षा नहीं, बल्कि मीडिया की स्वतंत्रता, आर्थिक दबाव, कानूनी वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट में मीडिया स्वामित्व के केंद्रीकरण, पत्रकारों पर बढ़ते दबाव, कानूनी चुनौतियों और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए कठिन वातावरण जैसी चिंताओं का उल्लेख किया गया है।

आज देश में अनेक पत्रकार ऐसे हैं जो सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ मीडिया संस्थानों ने टीआरपी, सनसनी और राजनीतिक झुकाव को प्राथमिकता बना लिया है। परिणामस्वरूप जनहित के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और बहस का केंद्र अक्सर ऐसे विषय बन जाते हैं जिनका आम जनता की समस्याओं से सीधा संबंध नहीं होता।

यह भी सच है कि पत्रकारिता का संकट केवल सरकारों या संस्थानों की वजह से नहीं है। समाज और मीडिया उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है। जब दर्शक तथ्य आधारित समाचारों की जगह मनोरंजन और उत्तेजना को प्राथमिकता देते हैं, तब मीडिया संस्थान भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। इसलिए पत्रकारिता को बचाने की जिम्मेदारी पत्रकारों के साथ-साथ समाज की भी है।

लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता किसी सरकार के विरोध का नाम नहीं है। स्वतंत्र पत्रकारिता का अर्थ है – जहां आवश्यकता हो वहां प्रशंसा, और जहां आवश्यक हो वहां कठोर सवाल। पत्रकार का दायित्व किसी दल, व्यक्ति या विचारधारा के प्रति नहीं, बल्कि सत्य और जनता के प्रति होता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे में प्रेस स्वतंत्रता की वैश्विक रैंकिंग में लगातार निचले पायदानों पर बने रहना चिंता का विषय है। यह समय आत्ममंथन का है। पत्रकारिता का स्तर नहीं गिरा है, बल्कि सच के प्रति जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता कमजोर हुई है। यदि पत्रकारिता को फिर से सम्मान और विश्वास दिलाना है, तो उसे सत्ता के गलियारों से निकलकर जनता के बीच लौटना होगा।

पत्रकारिता का भविष्य कैमरों, स्टूडियो और डिजिटल तकनीक से नहीं, बल्कि उस साहस से तय होगा जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता हो। लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है।

क्या रवि लामिछाने की भारत यात्रा से सुलझेगा नेपाल - भारत का सीमा विवाद

नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज 1 जून को भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद सत्ताधारी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की यह पहली भारत यात्रा है। लामिछाने का दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री बालेन शाह के संसद में पहले भाषण में भारत को लेकर दिए बयान पर नेपाल की राजनीति गरमाई हुई है। लामिछाने का यह दौरान भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गद्दीन के निमंत्रण पर हो रहा है। नई दिल्ली प्रवास के दौरान लामिछाने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विरूज मिश्रा और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करने की उम्मीद है। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत करेंगे। लामिछाने के बीजेपी मुख्यालय जाने की भी उम्मीद है।

अशोक भाटिया
यात्रा से परिचित सूत्रों का कहना है कि लामिछाने की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक आयोजित करने के प्रयास जारी हैं। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस यात्रा के दौरान लामिछाने की पहली निकाता फौजल, ऋषक के महासचिव बिपिन आचार्य, सांसद दीपक बोहरा और प्रदीप आचार्य साथ रहेंगे। गौरतलब है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संसद में सीमा विवाद को लेकर कहा था कि नेपाल ने भी भारत की जमीनों पर कब्जा किया है। इस बयान से नेपाल विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद अब वहां के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर सफाई भी दी । रविवार को एक बयान जारी करते हुए विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री शाह की टिप्पणी दोनों देशों के बीच नो-मैन्स लैंड और सीमा पार के कब्जे से जुड़ी हुई थी। बयान में कहा गया कि भारत के साथ नेपाल की वर्तमान सीमा 1816 की सुगौली संधि पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान में कहा, नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी और सुस्ता ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सीमांकन किया जाना अभी बाकी है। नेपाल और भारत दोनों ने कूटनीतिक माध्यमों और आपसी चर्चा से सीमा मुद्दों को सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई है। नेपाली प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के बाद नेपाल में विवाद शुरू हो गया है। नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बालेन शाह की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबूत पेश करने चाहिए या अपना बयान वापस लेना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा

विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की एक टिप्पणी अब एक ओर ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल भारत ने ही नहीं, बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। संसद में दिए गए उनके बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय को आधिकारिक सफाई जारी करनी पड़ी। ज्ञात हो कि इस वर्ष नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने बालेन शाह पहली बार अपने देश की संसद को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर जारी सीमा विवाद का जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों को मित्रतापूर्ण बातचीत की सलाह दी, लेकिन इसी दौरान दिया गया उनका एक बयान चर्चा का विषय बन गया। 35 वर्षीय प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। उनके अनुसार, केवल भारत ने ही नेपाली क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और विशेषज्ञों की मदद से तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और फिर मित्र देशों की तरह बैठकर इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। बालेन शाह ने नेपाल संसद को बताया कि नेपाल ने सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को चीन और ब्रिटेन के समक्ष भी उठाया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को इस पर रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा उसी समय का है, जब उन्होंने देश छोड़ा था। ब्रिटेन का उल्लेख उन्होंने क्षेत्र में उसके औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में किया।

प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर नेपाल की राजनीति में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली। नेपाली कांग्रेस की बसना थापा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रमेश मल्ल समेत कई विपक्षी सांसदों ने बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री या तो अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पेश करें या फिर बयान वापस लें। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी कथित तौर पर प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग कर डाली । नेपाल-भारत सीमा मामलों के विशेषज्ञ और भूगोलवेत्ता बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किए जाने का कोई उदाहरण नहीं है। हालांकि, उन्होंने माना कि कुछ सीमावर्ती इलाकों में सीमा स्तंभों के गायब होने और लोगों के आवागमन के कारण दोनों देशों के किसानों ने एक-दूसरे की जमीन का उपयोग किया है, लेकिन इसे सरकारी स्तर पर अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। ईडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने संबंधी कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत और नेपाल के बीच लगभग 97 प्रतिशत सीमा विवाद पहले ही सुलझाए जा चुके हैं। कुछ इलाकों में सीमा स्तंभों के अभाव के कारण भूमि उपयोग में ओवरलैप हो सकता है, लेकिन नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जे का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान के कुछ घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशय यह नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक तौर पर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने

सीमा क्षेत्र में मौजूद 'नो मैन्स लैंड' और दोनों देशों के लोगों द्वारा एक-दूसरे की जमीन के उपयोग से जुड़ी परिस्थितियों का उल्लेख किया था। साफाई में कहा गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारतीय नागरिकों द्वारा उपयोग की जा रही भूमि नेपाल की सीमा में आती हो और इसी तरह कुछ नेपाली नागरिक भारतीय क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग कर रहे हों। मंत्रालय ने इसे 'सीमा पार भूमि उपयोग' और 'क्रॉस-बॉर्डर ऑक्क्युपेशन' से जुड़ा मामला बताया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों देशों की तकनीकी टीमों और सीमा संबंधी तंत्र सीमा स्तंभों की मरम्मत, निर्माण और दशगणा क्षेत्रों से जुड़े आंकड़े एकत्र करने का काम लगातार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ सप्ताह पहले ही नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अधिभूत हिस्से हैं। वहीं, भारत का कहना है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं।

दोनों देश इन क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। भारत, चीन और नेपाल के त्रि-जंक्शन के निकट स्थित ये क्षेत्र कई वर्षों से विवाद का केंद्र रहे हैं। जून 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया था। भारत ने नेपाल के इस दावे को खारिज करते हुए इसे एकतरफा और कृत्रिम रूप से सीमा विस्तार का प्रयास बताया था। भारत का कहना है कि इन क्षेत्रों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के जरिए होना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित। संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।